क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रेस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्प्लेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक

क्रांति समय

RNI.No.: GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्प्लेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480   सह संपादक : संदीप मौर्या   E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 274, सोमवार, 29 अक्टूबर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.   रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

पुलवामा में आतंकियों ने की सीआईडी अधिकारी की हत्या, शव बरामद

एजेंसी,श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में एक सीआईडी अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि जिले के चेवा- कलां क्षेत्र से सीआईडी विभाग में कार्यरत इम्तियाज अहमद मीर का शव बरामद हुआ। वह श्रीनगर के शीरगाडी में सीआईडी में तैनात थे। अधिकारियों के अनुसार जब वह घर लौट रहे थे तब उन्हें निशाना बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरु कर दी है।

शोपियां में सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमला

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार को आतंकवादियों ने सेना के एक गश्ती दल पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के पोटेरवाल गांव में आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर गोलियां चलायीं। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सेना ने हमले का जवाब दिया जिसके बाद आतंकवादी वहां से भाग गए। उन्होंने बताया कि घटना में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है।

एबीवीपी-डूसू के मिशन साहसी प्रशिक्षण की तैयारी जोरों पर

नई दिल्ली। छात्र संगठन एबीवीपी व डूसू के संयुक्त तत्वावधान में दिल्ली में आयोजित होने वाले ''मिशन साहसी' प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। रविवार से दिल्ली में छात्राओं को आत्मरक्षा तथा स्वावलंबन के गुर सिखाने के लिए ''मिशन साहसी' का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। दिल्ली विविद्यालय के नॉर्थ 400 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षित छात्राएं 29-30 अक्टूबर को डीयू के कैम्पस के दौलतराम कॉलेज व साउथ कैम्पस के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में आयोजित होने वाले शिविरों में हजारों छात्राओं को प्रशिक्षण देने में मदद करेंगी।

2 नवंबर को दिल्ली विविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में स्थित पोलो ग्राउंड में एक मेगा प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा, जिसमें लगभग 10 हजार छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा । 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य आयोजित होने वाला यह पूरा कार्यक्रम शिफू जी शौर्य भारद्वाज व उनकी टीम की देखरेख में होगा।

मंत्री के औचक निरीक्षण में तीन साइटों पर मिले प्रदूषित धूल के कण

नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन के औचक निरीक्षण के दौरान धूल नियंतण्रमानक उल्लंघन के कई गंभीर मामले पाए गए। मंत्री कार्यालय की ओर से दी गई सूचना के अनुसार शनिवार को पर्यावरण मंत्री की अगुवाई में एक टीम ने कुछ इलाकों में निरीक्षण किया जिसमें मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने बुराड़ी क्रासिंग के पास तीन

कंक्रीट प्लांट (आरएमसी) ऑपरेट होते पाए गए जहां ऑपरेटर ने प्लांट से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था। टीम में मंत्री के साथ बुराड़ी के उपजिलाधिकारी, दिल्ली प्रदूषण नियंतण्र समिति और दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे।

भारत-जापान वार्षिक शिखर बैठक के लिए शनिवार को टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया।

कांग्रेस पर अमित शाह का निशाना, बोले- आपको नहीं देंगे साढ़े चार साल का हिसाब

एजेंसी,तेलंगाना। आगामी विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तेलंगाना में पार्टी की साख मजबूत करने में लगे हैं। अमित शाह आज भाजयुमो की ओर से सिकंदराबाद में आयोजित विजय लक्ष्य 2019 युवा महा अधिवेशन में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चार पीढ़ी तक देश पर शासन किया और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हम साढ़े चार सालों का हिसाब नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है। शाह ने अधिवेशन में उमड़ी जनता की भीड़ को देखकर कहा कि आज की ये सभा देख मैं कह सकता हूं कि 2019 के मई महीने में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले है। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार ने

हैदराबाद लिबरेशन डे मनाना बंद कर दिया क्योंकि वो ओवैसी से डरते हैं। आयुष्मान भारत का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि इस योजना से देश के 50 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद वो स्थल है जहां से सरदार पटेल जी ने भारत को एक करने का सिंहनाद किया था और निज़ाम को दुम दबाकर भागना पड़ा था। आज देश में दो विचारधाराएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, एक भाजपा है जो देश के विकास के लिए परिश्रम कर रही और दूसरा एक महागठबंधन बना है जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है वो भी तय नहीं है।

चारा घोटाले का पैसा सभी दलों ने खाया पर जो धराया, वो सजा काट रहा है : सांसद अरुण कुमार

पटना। बिहार के जहानाबाद से सांसद डॉ अरुण कुमार ने रविवार को गांधी मैदान में आयोजित एक रैली के दौरान एनडीए से दूरी के संकेत दे दिए। सांसद ने कहा कि चारा घोटाले का पैसा सभी दलों ने खाया पर जो धराया, वो सजा भुगत रहा है। आपको बता दें कि सांसद अरुण कुमार राष्ट्रीय समता पार्टी (सेक्यूलर) के नाम से नई पार्टी का गठन कर चुके हैं। गांधी मैदान में रैली के दौरान सांसद अरुण केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि ये सरकार अब नहीं आने वाली है। हमें टिकट की चिंता नहीं है बल्कि सड़क पर रहकर सरकार की बखिया उधेड़ेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब सांसद कुमार ने सरकार के खिलाफ बोला है। इससे पहले डॉ. कुमार अपनी नई पार्टी के गठन के मौके पर बिना नाम लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा पर भी जमकर हमला बोला था। कहा था कि जनमत को सीट और वोट की चिंता नहीं होती है। सिर्फ जनहित की चिंता होती है। शासन के लोग दिल पर हाथ रखकर कहें, शिक्षा का हाल पहले से बेहतर किया या सरकारी स्कूलों को और पीछे धकेल दिया है। रोज हत्याएं हो रही हैं। छह लोगों की हत्या करने वाला प्रशासन के साथ घूमता है। पुलिस दारू और बालू में फंसी है। सुशासन बाबू एक्शन में नहीं आए तो जनता फैसला लेगी। उपेन्द्र कुशवाहा का नाम लिये बिना उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जगदेव प्रसाद की जाति में पैदा होकर ही खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा मान बैठे हैं। ऐसा नहीं है, उसके लिए कर्म करना होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण ने अपनी आठ सौ बीघा जमीन बांट दी और ऐसे लोग आठ सौ बीघा जमीन बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि नई पार्टी को समर्थन देने के लिए उत्तर-पूर्व, बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी जार्ज फर्नांडिस की विचारधारा वाले लोग आये। कई संगठन और दलों ने भी समर्थन दिया है।

धार्मिक स्थल में छिपा था मासूम बच्ची का दुष्कर्मी हत्यारा

एजेंसी,इंदौर। अपहरण और दुष्कर्म के बाद यहां चार वर्षीय बच्ची की हत्या के सनसनीखेज मामले में फरार युवक को मध्यप्रदेश के रतलाम जिले से रविवार को धर दबोचा गया। पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) सिद्धार्थ बहुगुणा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मामले के आरोपी हनी अठवाल (25) को रतलाम जिले के जावरा कस्बे से वहां की स्थानीय पुलिस की मदद से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि वारदात के संबंध में आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इस बीच, पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि फरार होने के बाद अठवाल इंदौर से करीब 175 किलोमीटर दूर जावरा के धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी पहुंचा था, ताकि वह गिरफ्तारी से बच सके।

जावरा के शहर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) आशुतोष बागड़ी ने बताया, आरोपी शनिवार रात हुसैन टेकरी में ही छिपा था, जहां चेहल्लुम के धार्मिक आयोजन को लेकर फिलहाल श्रद्धालुओं की खासी भीड़ है। उन्होंने बताया कि अठवाल को सादे कपड़ों में तैनात पुलिस की खुफिया टीम ने जावरा के बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया, जब वह संभवतः रतलाम शहर के लिये रवाना होने की फिराक में था। बागड़ी ने कहा, पूछताछ के बाद पहली नजर में लगता है कि आरोपी छोटी बच्चियों को लेकर यौन मनोविकृति का शिकार है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अठवाल ने इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची को उसकी ट्यूशन की छुट्टी के बाद गुरुवार शाम अगवा किया था। उसने बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गयी थी।

बच्ची का शव एक नाले के किनारे शनिवार को मिला था। उन्होंने बताया कि आरोपी बच्ची के परिवार का परिचित है। बच्ची उसे मामा कहती थी। इसके चलते वह उसके साथ चलने को राजी हो गयी थी। अधिकारियों ने बताया कि हनी, मंदसौर में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में कुछ साल पहले भी पकड़ा जा चुका है। हालांकि, इस वारदात के वक्त वह नाबालिग था। इसलिये उसे सख्त सजा नहीं मिली।

जींद: 12वीं की छात्रा से किया गैंगरेप, हाथ-मुंह बांधकर तालाब में फेंका

जींद । एजेंसी। हरियाणा के जींद जिले के जुलाना क्षेत्र में 12वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप के बाद उसके हाथ-मुंह को बांधकर तालाब में फेंक कर जान से मारने का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन युवकों के खिलाफ गैंगरेप और अपहरण करके जान से मारने का प्रयास का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसी के गांव के दो युवक मोटरसाइकिल पर उसका अपहरण करके खेतों में बने एक कमरे में ले गए जहां चार युवक पहले से मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि इस दौरान दो युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया और चारों युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बलात्कार के बाद आरोपियों ने कपड़े से उसके मुंह और हाथ-पैर बांधकर गांव के तालाब में डालकर मारने का प्रयास किया। लेकिन छात्रा के परिजन उसकी तलाश करते हुए वहां पहुंच गए जिसके बाद सभी आरोपी युवक भाग गए। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर गांव के ही छह युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

दो लोगों ने किया रेप

छात्रा ने बताया कि दीपक और प्रवीण ने उसके साथ दुष्कर्म किया और कपिल, संजीव, छोटू व नसीब ने उसके साथ छेडखानी की। पुलिस ने कहा कि नाबालिग के साथ दरिंदगी करने के आरोप में गांव बूढ़ा खेड़ा निवासी दो मुख्य आरोपियों दीपक और प्रवीण तथा छेड़छाड़ के चार अन्य आरोपियों कपिल, संजीव, छोटू व नसीब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक पुष्पा खत्री ने बताया कि जुलाना के एक गांव निवासी पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दरिंदगी व छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

सांसद ने कहा, कुलपति जी तदर्थ शिक्षकों को नियमित करें

नई दिल्ली। दिल्ली विविद्यालय व सम्बद्ध कॉलेजों में वर्षो से अपनी सेवाएं दे रहे तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कुलपति प्रो. योगेश त्यागी से अनुरोध किया है और इस संबंध में सांसद ने कुलपति को पत्र लिखा है।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुआ हादसा

बिहार: मुंगेर सांसद वीणा देवी के बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत

पटना ग्रेटर। बिहार में मुंगेर सांसद वीणा देवी और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के बेटे आशुतोष कुमार की शनिवार को ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई मृतक आशुतोष कुमार ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था।

जानकारी के अनुसार, कोतवाली एक्सप्रेसवे एसएचओ हंसराज भदौरिया ने बताया कि मुंगेर से सांसद वीणा देवी व पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का बेटा आशुतोष कुमार ग्रेटर नोएडा में रहता था। वह शारदा यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनल ईयर का छात्र था शनिवार सुबह करीब 3:30 बजे वह परी चौक से ग्रेटर नोएडा की तरफ एक्सप्रेस-वे होते हुए क्रेटा कार में सवार होकर जा रहा था।

अभी वह सेक्टर-128 स्थित जेपी हॉस्पिटल के पास पहुंचा ही था कि उसे नींद की झपकी आ गई।

इसके चलते उसकी कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

आनन-फानन में उसे पास के जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

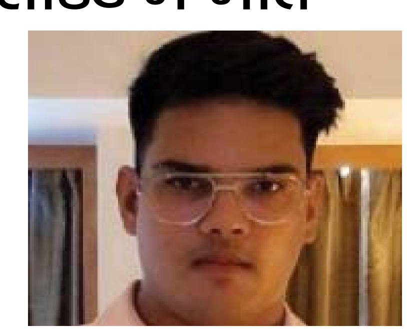

पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के बेटे आशुतोष कुमार की शनिवार को ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई मृतक आशुतोष कुमार ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था।
बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिजन शव को लाने के लिए।

पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिजन शव को लाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है।

»»» अब कम होगी कालका से शिमला की दूरी

नई तकनीक के साथ कई सुधार कर रहा रेलवे

नई दिल्ली, एजेंसी। रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कालका-शिमला रेलखंड की 96 किलोमीटर की दूरी को तीन घंटे में पूरा कराने की कवायद में जुटा है।

इसके लिए नई तकनीक के तहत रेलवे ट्रैक की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है और रेल पटरियों व स्लीपर में आवश्यक सुधार किया जा रहा है।

हाल ही में कालका-शिमला रेलमार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस ट्रैक पर चलने वाली गाड़ियों का समय पांच घंटे से कम करके तीन घंटे करने की संभावनाएं तलाशने को कहा था।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस साल के अंत तक इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी जानी है। फिलहाल ट्रायल किए जा रहे हैं। शिमला से शोघी के बीच रफ्तार बढ़ाने के लिए ट्रैक को बेहतर बनाया जा रहा है। 22 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर चेकरेल डाला जा रहा है, ताकि तेज गति से चल रही ट्रेन तीव्र घुमाव पर संतुलन बरकरार रखे। रेलवे अधिकारियों को उम्मीद है कि चेकरेल तकनीक से यहां गति बढ़ाई जा सकेगी।

रेलवे के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शिमला-कालका रेलमार्ग पर जेडबीएम-3 इंजन चलता है जिसकी क्षमता 40 किलोमीटर प्रतिघंटा है। लेकिन घुमावदार मार्ग होने के कारण इसकी रफ्तार कम रखनी पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में ही पठानकोट-जोगिंदर नगर रेलमार्ग पर जेडबीएम-3 इंजन चलता है लेकिन इसकी गति अधिक रहती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के बावजूद यह रेलमार्ग बिल्कुल सीधा है।

पारदर्शी कोच से मिलेगा नजारा

शिमला-कालका रेलमार्ग पर रेलवे ट्रैक की ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही पटरियों के बीच रोड़ी एवं पत्थर भी डाले जा रहे हैं, ताकि इसे मजबूती प्रदान की जा सके। इसके अलावा रेलवे इस ट्रैक पर जल्द ही पूर्ण पारदर्शी कोच उतारेगा। यात्री इस कोच में बैठकर कालका-शिमला मार्ग में पड़ने वाले मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकेंगे।

रेलवे लेह में वायुदाब नियंत्रण वाले कोच चलाएगा

रेलवे ने चीन सीमा पर दुनिया की सबसे ऊंची बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन पर चलने वाली ट्रेनों में विमानों की तरह ही वायु दाब नियंत्रण वाले कोच का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।

इस रेलवे ट्रैक पर वायु दाब नियंत्रण वाले कोच से यात्रियों को सांस लेने में परेशानी नहीं होगी।

योगी के बयान पर बोली कांग्रेस, ये दुखद छ्रूको संविधान का ज्ञान नहीं

विमानों के केबिन में वायु दाब नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर वायु का घनत्व कम होता है। इससे होने वाली परेशानियों से बचने के लिए विमानों के केबिन में समुद्र की सतह के समान दबाव समायोजित किया जाता है। दोनों जगहों पर सांस लेने की स्थिति लगभग समान होती है।

समुद्र की सतह से 5,360 मीटर की ऊंचाई पर 83,360 करोड़ रुपये की लागत से 465 किलोमीटर रेल लाइन बनाई जाएगी जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगी।

इसी रेल लाइन में रेलवे देश में पहली बार, वायु दाब नियंत्रण वाले कोच का उपयोग ट्रेनों में करेगा।

इस समय केवल चीन में किंघाई-तिब्बत रेलवे लाइन में इस तरह के कोच का इस्तेमाल किया जाता है।

उत्तर रेलवे के चीफ इंजीनियर (निर्माण) डी.आर. गुप्ता ने बताया कि ऊंचाई वाले स्थानों में यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से विशेष दाब नियंत्रण वाले कोच लगाने की योजना है। इससे कोच के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी।

पटना : इंडियन पीपुल्स थियेटर एसोसिएशन के प्लेटिनम जुबली समारोह के मौके पर संस्कृति मार्च में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री एवं समाजसेवी शबाना आजमी।

संपादकीय

चिदंबरम पर शिकंजा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जाना एक महत्त्वपूर्ण घटना है। हालांकि यह प्रश्न तो बना हुआ है कि अगर मामले में ईडी के पास सबूत थे तो आरोप पत्र में इतनी देरी क्यों हुई? वैसे चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी पहले ही आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र दाखिल कर चुका है। यह मामला सीबीआई एवं ईडी दोनों के पास है।

सीबीआई ने चिदंबरम पिता-पुत्र के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया हुआ है। इस तरह देखें तो आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस दोनों में पिता-पुत्र के खिलाफ कानूनी वौंकि कस चुका है। आईएनएक्स मामले में तो चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 नवम्बर तक बढ़ा दिया है। आरोप अत्यंत गंभीर हैं। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम ने विदेशी निवेशकों के साथ सांठ-गांठ कर उनके उद्यमों को मंजूरी दिया और उसके बदले में धनशोधन किया। इस मामले में एस भास्करमन (चिदंबरम के पुत्र कार्ति के चार्टर्ड एकाउंटेंट), वी श्रीनिवासन (एयरसेल के पूर्व सीईओ), ऑगस्टस राल्फ मार्शल (मैक्सिस से जुड़े), मलयेशिया स्थित एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क, एयरसेल टेलीवेंचर लिमिटेड, मैक्सिस मोबाइल सर्विस एसबी, बूमि अर्मदा बेरहाद, बूमि अर्मदा नेवीगेशन एसबी आदि सभी को आरोप पत्र में शामिल किया गया है। अगर न्यायालय इस आरोप को स्वीकार कर लेता है तो इनके खिलाफ मुकदमा आरंभ होगा एवं गिरफ्तारी भी हो सकती है। आरोप यह है कि मार्च 2006 में बतौर वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने विदेशी निवेशक ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड, मॉरीशस को अवैध रूप से विदेशी निवेश संबर्धन बोर्ड का अनुमोदन नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से दे दिया। कायदे से ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड का निवेश प्रस्ताव आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के पास जाना चाहिए था। वहां से इसे स्वीकार किया जाता या अस्वीकार। जाहिर है, अगर ईडी का आरोप सही है तो यह मानना होगा कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते देश को धोखा दिया। उनके पुत्र इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे। देश चाहेगा कि इसकी कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी हो ताकि सच सामने आ सके।

प्रदूषण पर सख्ती

स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः देश में डेढ़ साल के भीतर वाहन और ईंधन गुणवत्ता को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में सख्त कदम उठा ही लिया। देश में ईंधन और इंजन गुणवत्ता के हिसाब से चौथे चरण मानदंडों वाले वाहन दौड़ रहे हैं जबकि विकसित देशों ने वे गुणवत्ता मानक अपने देशों में लागू कर दिये हैं, जिन्हें भारतीय मानक बीएस-5 से भी पूरा नहीं किया जा सकता। बीएस-6 का मतलब है यूरो 6 स्टैंडर्ड, जिसे भारत स्टेज-5 नाम दिया गया है। सन? 2000 में सरकार ने इंडिया 2000 नाम से प्रदूषण मानक निर्धारण प्रारंभ किया था, जिसे अगले ही साल 2001 में भारत स्टेज दो नाम से अपग्रेड कर दिया गया। 2005 में बीएस 3 और 2010 में आया बीएस-4। दस साल बाद सीधे आधुनिकतम मानक लागू करने की सोच के साथ सुप्रीमकोर्ट ने एक चरण आगे बढ़कर सीधे बीएस-6 मानदंडों को वाहन निर्माण से ईंधन उपलब्धता तक लागू करने में छूट देने से इनकार कर दिया। अधिकांश मेट्रो व बड़े शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति किसी से छुपी नहीं है। बीएस-6 मानदंड लागू होने के बाद पीएम 2.5 उत्सर्जन में 68 प्रतिशत सुधार की उम्मीद है।

दरअसल, दो साल पहले, सुप्रीमकोर्ट ने बीएस-5 मानदंडों को छोड़ने वाहन निर्माताओं को कहा था। उन्होंने एक साल की छूट अवधि मांगी थी। चूंकि ऑटो निर्माता 1 अप्रैल, 2020 तक बीएस-4 श्रेणी के सभी तैयार वाहनों से मुक्ति पाना चाहेंगे, लिहाजा उपभोक्ताओं को सस्ते वाहन खरीदने का एक अवसर भी मिलेगा। 31 मार्च 2020 के पहले सभी नए बीएस-4 वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकार भी इस मुद्दे पर अदालत के समान ही दृढ़ संकल्प दिख रही है। निश्चय ही 2019 में आम चुनावों के बाद जो भी सरकार आएगी, उसे वाहन निर्माताओं या रिफाइनरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और ज्यादा मोहलत की मांग व दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसका एक ही उपाय है गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया को तेज करना, ताकि आम चुनावों से पहले बीएस-6 गुणवत्ता का रोडमैप आकार ले ले।

ओशो

ज्ञानी-मुमुक्षु

नक ने कहा, ''हे प्रभो, पुरु ष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है। और मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? यह मुझे कहिए! एतत मम लूहि प्रभो! मुझे समझाएं प्रभो!' बारह साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना है: ''हे प्रभु! भगवान! मुझे समझाएं!एतत मम लूहि!मुझ नासमझ को कुछ समझ दें! मुझ अज्ञानी को जगाएं!' तीन प्रश्न पूछे हैं-''कथं ज्ञानम! कैसे होगा ज्ञान!' साधारणतः तो हम सोचेंगे कि ''यह भी कोई पूछने की बात है? किताबों में भरा पड़ा है।' जनक भी जानता था। जो किताबों में भरा पड़ा है, वह ज्ञान नहीं; वह केवल ज्ञान की धूल है, राख है! ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती है। राख इकट्ठी होती चली जाती है, शास्त्र बन जाती है। वेद राख हैं-कभी जलते हुए अंगारे थे। ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था। फिर राख रह गए। फिर राख संयोजित की जाती है, संगृहीत की जाती है, सुव्यवस्थित की जाती है। जैसे जब आदमी मर जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं-उसको फूल कहते हैं। बड़े मजेदार लोग हैं! जिंदगी में जिसको फूल नहीं कहा, उसकी हड्डियां-वड्डिया इकट्ठी कर लाते हैं-कहते हैं, ''फूल संजो लाए'! जनक भी जानता था कि शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी हैं। लेकिन उसने पूछा, ''कथं ज्ञानम? कैसे होगा ज्ञान?' क्योंकि कितना ही जान लो, ज्ञान तो होता ही नहीं। जानते जाओ, जानते जाओ, शास्त्र कंठस्थ कर लो, तोते बन जाओ, एक-एक सूत्र याद हो जाए, पूरे वेद स्मृति में छप जाएं-फिर भी ज्ञान तो होता नहीं।''कथं ज्ञानम? कुछ दिनों पहले कुछ जैन साध्वियों की मेरे पास खबर आई कि वे मिलना चाहती हैं, मगर श्रावक आने नहीं देते। यह भी बड़े मजे की बात हुई! साधु का अर्थ होता है, जिसने फिक्र छोड़ी समाज की; जो चल पड़ा अरण्य की यात्रा पर। लेकिन साधु-साध्वी कहते हैं, ''श्रावक आने नहीं देते! वे कहते हैं, वहां भूल कर मत जाना। वहां गए तो यह दरवाजा बंद!' यह कोई साधुता हुई? यह तो बड़ी उलटी बात हुई। यह तो ऐसा हुआ कि साधु श्रावक को बदले, उसकी जगह श्रावक साधु को बदल रहा है। एक मित्र ने आ कर मुझे कहा कि एक जैन साध्वी आपकी किताबें पढ़ती है, लेकिन चोरी से; टेप भी सुनना चाहती है, लेकिन चोरी से। और अगर कभी किसी के सामने आपका नाम भी ले दो तो वह इस तरह हो जाती है जैसे उसने कभी आपका नाम सुना ही नहीं। यह मुक्ति हुई?

संस्थानों की स्वायत्तता नष्ट करने के नतीजे

> ''हमारे संसदीय लोकतंत्र में तमाम तरह की संस्थाएं ऐसी निगरानी चौकियों की तरह हैं, जो लोकतंत्र को रास्ता भटकने से रोकती हैं, उसे सही राह की ओर प्रेरित करती हैं। लेकिन अगर इन संस्थाओं की ही राह मोड़ दी जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र किसी मंजिल की ओर बढ़ता दिखेगा। लेकिन यह नजारा बड़े भद्दे ढंग से हमारे दिखने लगा है। इसी साल की शुरुआत में देश के सर्वोच्च न्यायालय में वह नजारा दिखा था जब चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने प्रेस कांफ्रेस करके तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पर मर्यादाओं का पालन न करने और न्यायपालिका की स्वायत्तता और निष्पक्षता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। वह नजारा भी अभूतपूर्व था''

हरिमोहन मिश्र

बाव बढ़ेगा तो प्रेशर कूकर फट पड़ेगा। पिछले महीने ही यह चेतावनीनुमा टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई थी। मामला चर्चित भीमा-कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का था। लेकिन यह चेतावनी इतनी जल्दी किसी और स्वरूप में अपनी पूरी विद्रुपता के साथ हकीकत में प्रकट होगी, यह किसने अंदाजा लगाया था? अभूतपूर्व सीबीआई संकट क्या किसी भयावह विस्फोट से कम है? क्या यह हमारी पूरी व्यवस्था के चरमरा जाने और संस्थाओं के ढहते जाने का ही दर्दनाक नजारा नहीं है? लेकिन ठहरिए, अभी तो शायद ऐसे और नजारे दिखने बाकी हैं या जो जारी हैं मगर बड़ी चर्चाओं से गायब हैं। अब एक और चेतावनी अर्थव्यवस्था के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर विराल आचार्य की ओ[illegible] है। उन्होंने हाल में मुंबई में ए.डी. शर्राफ स्मृति व्याख्यानमाला में कहा कि जो सरकारें केंद्रीय बैंक का मान नहीं रखतीं, उन्हें देर-सबेर पूंजी बाजारों का अभिशाप झेलना पड़ता है, वे भयावह आर्थिक बदहाली को बुलावा दे बैठती हैं और उस दिन को कोसती हैं, जब उन्होंने महत्त्वपूर्ण नियामक संस्था को नीचा दिखाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बाजार सरकार को अनुशासित कर सकता है कि वह केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता पर चोट न करे और वह सरकार को जबरन दखलंदाजी के लिए दंडित भी कर सकता है। इस बयान में केंद्रीय बैंक की जगह देश की अहम संस्थाएं रख दें, और बाजार की जगह जनता रख दें तो खासकर चुनावी वर्ष में यह बड़े व्यापक संदेश देता है, जो सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी को असहज कर सकता है। दरअसल, हमारे संसदीय लोकतंत्र में तमाम तरह की संस्थाएं ऐसी निगरानी चौकियों की तरह हैं, जो लोकतंत्र को रास्ता भटकने से रोकती हैं, उसे सही राह की ओर प्रेरित करती हैं। लेकिन अगर इन संस्थाओं की ही राह मोड़ दी जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र किसी मंजिल की ओर बढ़ता दिखेगा। लेकिन यह नजारा बड़े भद्दे ढंग से हमारे दिखने लगा है। इसी साल की शुरुआत में देश के सर्वोच्च न्यायालय में वह नजारा दिखा था जब चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने प्रेस कांफ्रेस करके तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पर मर्यादाओं का पालन न करने और न्यायपालिका की स्वायत्तता और निष्पक्षता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। वह नजारा भी अभूतपूर्व था। अब उस संस्था की तबाही का नजारा प्रस्तुत हो गया है, जो सत्ताधारियों के पद के दुरूपयोग पर नजर रखने के लिए स्थापित की गई है। न यह पहली बार है कि ऐसी संस्थाओं को धूमिल किया गया है, न इसके संभावित राजनैतिक नतीजों की बातें ही कोई नई हैं। यूं तो इसके नजारे हर दौर में दिखते रहे हैं, लेकिन इसका भयावह रूप इमरजेंसी में प्रकट हुआ था। उसके राजनैतिक नतीजे भी 1977 में दिख गए थे जब कांग्रेस का सफाया हो गया था। वह दौर भी उसी केंद्रीकरण और मजबूत नेतृत्व की दलील के साथ आया था, जिसकी चर्चाएं आज भी खुलकर पेश की जा रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि देश को मजबूत निर्णायक नेतृत्व की अभी कम से कम दस तक शासन करने की दरकार है क्योंकि अस्थिर सरकारों और कमजोर गठबंधन देश को तबाही के रास्ते पर ले जाते हैं और उसे विकास के रास्ते से भटका देते हैं। लेकिन हुजूर, मजबूत नेतृत्व के नजारे तो हम देख ही रहे हैं। इसलिए यह दलील हमेशा तबाही की ओर ले जाती रही है और वास्तव में विकास के रास्ते से भटकाती रही है। ऐसे दौर में भ्रष्टाचार भी खुलकर खेलता है, इसके नजारे न जाने कितनी बार [illegible]

भरमार है, बल्कि अर्थव्यवस्था और लोगों की माली हालत पर भी इसका बुरा असर दिख रहा है। कृषि अर्थव्यवस्था और असंगठित क्षेत्र के उद्योगों खासकर छोटे और मझोले उद्योगों की खस्ताहाली से चारों तरफ असंतोष फैल रहा है। संगठित उद्योगों और उत्पादन क्षेत्र के लगातार सिकुड़ने से पढ़े-लिखे नौजवानों की बेरोजगारी भी बेपनाह होती जा रही है। अब इन बातों को आंकड़ा से साबित करने की जरूरत भी नहीं रह गई है। सरकार भी अब इसे आंकड़ा मकड़जाल में छुपाने या वृद्धि के दावे करने से बचने लगी है। पांच राज्यों के चुनावों में जारी प्रचार अभियान को ही गौर कर लीजिए। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता दूसरे तरह के फसाने तलाश करने की कोशिश करते दिखते हैं। वे घुसपैठियों और गठबंधनों की अफरातफरी और अस्थिरता का हवाला दे रहे हैं।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो सीबीआई में जारी जंग पर अपना मुंह खोलने से बच रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सरकार के किए कई तरह के अंकुश जड़ दिए हैं, बल्कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तक पर सीमाएं लगा दीं। सीवीसी की ओर से पेश इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार दिया कि इससे सीवीसी संस्था प्रभावित होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह दलील भी नहीं मानी कि सीवीसी को जांच के लिए कम-से-कम तीन हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए। पहले अदालत दस दिन की ही मोहलत देना चाहती थी लेकिन बहुत गुजारिश करने पर दो हफ्ते का समय देने को तैयार हुई। असल सीबीआई के इस प्रकरण ने सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसी की ही साख मटियामेट नहीं की, बल्कि सीवीसी की भी साख पर सवालिया निशान लगा दिया। सीवीसी संस्था का गठन भी राजनैतिक नेतृत्व और कार्यपालिका के पद के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। विनीत नारायण वाले मुकदमे में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की निगरानी का काम सीवीसी को इसीलिए सौंपा था, ताकि उसे राजनैतिक नेतृत्व की दखलंदाजी से बचाया जा सके। मगर इस प्रकरण ने उसकी उस भूमिका पर ही संदेह कायम कर दिया। आखिर सीवीसी अगर सीबीआई के विशेष निदेशक आर.के. अस्थाना की निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ शिकायत पर समय रहते गौर कर लेती तो शायद यह हालात पैदा नहीं हो पाती। लेकिन पता यह भी चल रहा है कि वह कथित तौर पर आलोक वर्मा को फंसाने की साजिश का हिस्सा थी और उसके लिए सबूत अभी जुटाए ही जा रहे थे। इसकी भनक आलोक वर्मा को लग गई तो उन्होंने उन्हीं गवाहों कथित तौर पर हैदराबाद के व्यापारी पर डोरे डाले, उसे पकड़ा तो उसने उलटा बयान दिया, जिसे उन्होंने अस्थाना और उनके साथ के अफसरों पर एफआईआर का आधार बनाया। यही नहीं, इस कहानी के लपेटे में ईडी के अधिकारी भी हैं।यानी इन संस्थाओं के राजनैतिक दुरूपयोग का जो आरोप विपक्ष लंबे समय से लगाता आ रहा था, वह लगभग खुलकर सामने आ गया। लिहाजा, सरकार की विश्वसनीयता पर भी गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। यह आरोप भी साबित होने लगा है कि कैसे पीएमओ में ही सारी शक्तियां सिमट गई हैं? पीएमओ ही सारे निर्णय ले रहा है और वह उन मर्यादाओं का भी पालन नहीं कर रहा है जो कानूनन बेहद जरूरी हैं। मसलन, सीबीआई निदेशक को ही छुट्टी पर भेजने से पहले नियुक्ति समिति से सलाह ली जानी थी, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश हैं। इसके मायने तो हैं कि शक्तियों के केंद्रीकरण से न सिर्फ लोकतंत्र बदहाल होता है, बल्कि विकास भी अवरूद्ध या एकतरफा होता है। इसके नजारे भी दिख ही रहे हैं। अर्थव्यवस्था बदहाल है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान हैं लेकिन हाल में ही आई रिपोटरे के अनुसार कुछ उद्योग घरानों की संपत्ति बढ़ती जा रही है। मतलब यह कि केंद्रीकरण, निर्णायक नेतृत्व और स्थिर मजबूत सरकारें विकास की राह से भटक जाती हैं।

प्रसंगवश

सीखने-सिखाने का रस

गिरीश्वर मिश्र

जीवन और साहित्य, दोनों में रस का बड़ा महत्त्व है। न नीरस साहित्य मन को अच्छा लगता है, न नीरस जीवन। दोनों का अंतिम उद्देश्य सुख और आनंद यानी रस की साधना ही करना है। इसलिए रस का विचार प्राचीन काल से भारतीय चिंतन में विस्तृत विवेचन का केंद्र बना रहा तो कोई आश्चय की बात नहीं लगती। परंपरागत साहित्य में उसके स्वरूप, प्रकार, प्रस्तुति, अनुभूति और समाज में उसके विस्तार की व्याख्या साहित्यिक और आध्यात्मिक, दोनों ही स्तरों पर की जाती रही है। रस की निष्पत्ति कैसे होती है, यह भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना ''नाटय़शास्त्र' और आचार्य अभिनवगुप्त और अन्यान्य साहित्य शास्त्रियों और नाटय़ मर्मज्ञों द्वारा विवेचित होता रहा है। साहित्य शास्त्र में रस को ''काव्य की आत्मा' कहा गया है। रस का आस्वाद मन को तृप्त और हर्षित करता है। रस की पूरी प्रक्रिया या व्यापार तरल, रु चिर, प्रिय, सुंदर है, और उसके साथ सभी का राग और स्नेह होता है। वे सभी रस के अनुभव को आठ या दस स्थायी भावों से जोड़ते हैं। इनमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत तो सभी मानते हैं। कुछ विचारक शांत और कुछ वात्सल्य को भी इस सूची में शामिल कर लेते हैं। इस सूची में सीखने-सिखाने के बारे में सीधे-सीधे कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि यह मानव जीवन का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण पक्ष है, खास तौर पर तब जब शिक्षा केंद्र हिंसा, आक्रोश, असहिषणुता और भेदभाव के केंद्र से बनने लगे हैं, तो शिक्षा में खुशी की अनुभूति और आह्लाद का वातावरण तैयार करना जरूरी हो गया है।आधुनिक मनोविज्ञान की संवेगों की सूची में प्रसन्नता, भय, आश्र्चय, दुख, वीभत्स, क्रोध, स्वीकृति और प्रत्याशा, इन आठ की गणना की जाती है। इन प्राथमिक संवेगों के अलावे शर्म, ग्लानि और गौरवबोध द्वितीयक संवेग कहे गए हैं। अक्सर इन संवेगों को प्रिय-अप्रिय और तीव्र-दुर्बल के आयामों पर रखा जाता है। चिंता, क्रोध और ईर्ष्या के संवेगों को लेकर काफी शोध किया गया है। पिछले कुछ सालों में प्रसन्नता या खुशी में शोधकर्ताओं ने रु चि ली है। खुशी की अनुभूति अपने समग्र जीवन के मूल्यांकन से उपजती है। हम अपनी जिंदगी को जितना ही ज्यादा पसंद करते हैं, उतनी ही खुशी मिलती है। धन या आर्थिक समृद्धि और खुशी के बीच में मध्यम दरजे का संबंध होता है। सुख की कामना और उसकी तलाश समूची मानव सभ्यता का लक्ष्य है। शिक्षा भी इसी से जुड़ी है, और शिक्षा के केंद्र में है सीखना-सिखाना। मनुष्य जन्म लेने के बाद जीवनपर्यंत शारीरिक और बौद्धिक कायरे को करना-सीखता रहता है। सीखना व्यापक प्रक्रिया है। हमारे जीवन की गुणवत्ता सीखने की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि मानवीय पूंजी के निर्माण के लिए सीखना पहली शर्त है। दुख और चिंता का विषय है कि आज प्राथमिक शिक्षा से ले कर उच्च शिक्षा तक का शैक्षिक परिवेश असमानता, असहिष्णुता, पर्यावरण-क्षरण, बाजारवाद और अपरिमित प्रौद्योगिक विकास के प्रभाव में किस्म-किस्म की प्रतिस्पर्धाओं, तरह-तरह के तनावों और असुरक्षाओं से ग्रस्त होता चला जा रहा है। शैक्षिक कार्य का अनुभव त्रासद होता जा रहा है, जिसमें से खुशी काफूर होती जा रही है। सीखने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे खुशी मिले या सीखना खुशी का स्त्रोत बन जाए। आज जब सामाजिक प्रगति और सामाजिक नीति की उपयुक्तता के पैमाने के रूप में खुशी को ग्रहण किया जा रहा है, तो हमें सीखने की प्रक्रिया और उसके किरदारों की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना होगा। सीखने का परिवेश स्नेहपूर्ण, मैत्री का अवसर देने वाला सुरक्षित तथा भरोसे वाला होना चाहिए। तभी प्रतिभाओं को निखरने और उनका उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। चूंकि मानवीय योग्यताओं में पर्याप्त अंतर और विविधता पाई जाती है, शिक्षा में नवोन्मेष और गुणवत्ता के लिए आवश्यक होगा कि छात्र-छात्राओं में मौजूद विविध प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं को पहचान कर उनका सम्मान किया जाए न कि सबको एक ही तरह समझा जाए। आज अनावश्यक रूप से ज्यादा कमाऊ किस्म की नौकरियों को ध्यान में रख कर छात्रों को प्रेरित और आकर्षित किया जाता है, जो कभी-कभी उनके स्वभाव के विरु द्ध भी होती हैं, और जिनके कारण कुंठा और तनाव पैदा होता है। व्यक्ति उन कायरे में लगन और आत्मविास के साथ अपना श्रेष्ठ योगदान तभी कर पाता है, जब उसे अपनी प्रकृति के अनुकूल कार्य चुनने का अवसर मिलता है।

बीच समय में

पूर्वोत्तर का हिन्दी से जुड़ाव

प्रो. चंदन कुमार

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है, जिसके संवर्धन के लिए प्रचार-प्रसार सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर पूरे भारत में होता रहा है। हिन्दी का समर्थन-विरोध गैर-हिन्दी प्रांतों में समय-समय पर होता रहा है। मणिपुर में हिन्दी के विकास को लेकर डॉ देवराज के विचारों से सहमत होते हुए कहा जाए तो माना जा सकता है कि पूर्वोत्तर का हिन्दी से लगाव बहुत पुराना यानी मुगलकाल से है। वैसे तो हिन्दी के विस्तार का काल भी भक्तिकाल ही है, जिसका समय मुगलों के समकालीन है। डॉ देवराज ने मुगल आक्रमण के दौरान उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के उत्तर-पूर्व को पलायन को आधार बताया है, जो एक ऐतिहासिक सत्य है। कहना गलत न होगा कि मुस्लिम आक्रमण के विरु द्ध हिन्दू धर्म की रक्षा का जो जतन उत्तर-पूर्व में हुआ है, वैसा भारत के अन्य हिस्सों में देखने को नहीं मिलता। दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य जिस तरह से हुआ है, विशेषकर स्वाधीनता के बाद सरकार के स्तर पर, उत्तर-पूर्व में उसका आधा भी नहीं हुआ। लेकिन स्थानीय स्तर पर जैसी प्रगति और जैसा लगाव उत्तर-पूर्व में देखने को मिलता है, शायद दक्षिण में वैसा नहीं मिलता। राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति के सम्यक अनुपालन की भावना पूर्वोत्तर के मानस की अलग और दिव्य पहचान है। यही कारण है कि वहां के लोगों के लिए हिन्दी से जुड़ना राष्ट्रीयता का सम्मान करने के साथ-साथ भारत की एकता और अखंडता को दृढ़ता प्रदान करने का साधन भी है। मणिपुर में हिन्दी अर्थात मध्यकालीन बोलियों का संपर्क ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी है, जबकि असम में भी मध्यकाल का समय तो यही है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण के समय से ही इसका संपर्क है। इस संदर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण नाम श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव का है। शंकरदेव का समय 1481 ई. में भारत यात्रा का है। शंकरदेव ने ब्रजावली की रचना में अखिल भारतीय स्तर की हिन्दी की बोलियों के शब्दों का उत्तम प्रयोग किया। शंकरदेव की रचनात्मकता में भारत वर्ष की वर्णन मिलता है, वे सिर्फ असम की बात नहीं करते। यही कारण है कि पूर्वोत्तर का हिन्दू अतीत न सिर्फ पुराना है, बल्कि वैचारिक स्तर पर बहुत सघन और आत्मीय भी है। भारतीय परंपरा में जिस जयंति मंगला काली भद्र काली की बात होती है, उसका प्रारब्ध मेघालय के जयंतिया समुदाय से है, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया जाता। इस तरह के अनेक पक्ष हैं, जो भारतीयता की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता के सूचक हैं। अरु णाचल नगालैंड, त्रिपुरा का संपर्क भी हिन्दी से कुछ इसी तरह हुआ। हिन्दी का व्यवस्थित विस्तार पूर्वोत्तर में स्वाधीनता के बाद और हिन्दी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दरजा मिलने के बाद हुआ है। इस तरह से हिन्दी को लेकर जो अभी स्थिति है, उसमें स्वाधीनता के बाद की स्थिति का विशेष योगदान है। असल में स्थिति कुछ और रही है। स्वाधीनता के बाद विकास के साथ उत्तर-पूर्व को भारत की मुख्यधारा के साथ ठीक से नहीं जोड़ा गया। एक तरह से उपेक्षा का भाव ही रहा। परिणामत वहां के जनमानस में व्यवस्था-विरोध के रूप में उभरा। किसी भी व्यवस्था के विरोध और समर्थन में भाषा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उत्तर-पूर्व में हिन्दी का समुचित विकास हुआ होता तो क्षेत्रीय स्तर पर जिस तरह के विरोध और अविास पैदा हुए, शायद नहीं होते। राजनीतिक स्तर पर उत्तर-पूर्व कई क्षेत्रों में कटा रहा जिसके कारण सत्ता और संस्कृति से लगाव की दिशा भटक गई। पिछले कुछ वर्षो में स्थानीय लोगों की जागरूकता और कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से उत्तर-पूर्व के लोगों में हिंदी के प्रति गहरी रु चि पैदा हुई है। इसका कारण भारत सरकार का राजभाषा आयोग नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो पूर्वोत्तर में व्यक्तिगत स्तर पर सक्रिय रहे। उनमें कुछ स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यकर्ता हैं। कुछ स्वयंसेवक भी हैं, जिनने अपना कार्यक्षेत्र पूर्वोत्तर को बनाया, कुछ पत्रकार तथा कुछ भारत सरकार के अधिकारी भी हैं। ये सभी वहां अपने व्यक्तिगत प्रयास की बदौलत के लोगों के बीच हिन्दी और उसके अतीत को जागृत करने में सफल हुए। वर्तमान समय में हिन्दी के प्रचारकों में एक बड़ा नाम नगालैंड के पियोंग टेमजन का है, जो पिछले 45 वर्षो से निर्बाध गति से हिन्दी की सेवा में जुटे हैं। हिन्दी के माध्यम से वहां के लोग सांस्कृतिक ऐक्य और उसकी जड़ की तलाश कर रहे हैं। भारतीय एकात्मकता के लिए यह एक सुखद पहलू है। इसे प्रेरित करने की जरूरत है, जिससे उत्तर-पूर्व के लोगों की पहुंच भारत के अन्य हिस्सों में भी बढ़े। पुरानी मान्यताओं को फिर से जीवित करने और इसकी पहचान के उन प्रतीकों को हिन्दी में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। हिन्दी में उनकी स्थानीय पहचान को लिखे जाने की जरूरत है। ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चिह्नों को हिन्दी में जगह देने की महती आवश्यकता है। यदि साहित्य, समाज और संस्कृति के स्तर पर ये प्रयास सफल होते हैं, तो निश्चित ही भारत की अखंडता और सांस्कृतिक एकता को बल मिलेगा। कहना न होगा कि ऐसा होने पर राष्ट्र के निर्माण के स्थायी उपादान का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत ने मालदीव में लोकतंत्र बहाल करने में मदद की: मामून अब्दुल गयूम

नई दिल्ली (एजेंसी)।

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम ने रविवार को कहा कि भारत ने मौजूदा शासन पर दबाव डाल कर मालदीव में लोकतंत्र बहाल करने में एक ''सकारात्मक भूमिका'' निभाई। साथ ही, इस द्वीपीय देश की नयी सरकार नयी दिल्ली की चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहेगी। अदालती आदेश के बाद जेल से 30 सितंबर को रिहा होने के करीब महीने भर बाद गयूम ने कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने मालदीव को भारी नुकसान पहुंचाया। आखिरकार, लोकतांत्रिक ताकतों की जीत हुई।

गयूम ने मालदीव में 2008 तक और करीब तीन दशक तक शासन किया। वह 2008 में देश के प्रथम बहुदलीय चुनाव में हार गए थे। यामीन के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत इस साल फरवरी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। विपक्ष के संयुक्त नेता इब्राहीम मोहम्मद सोलिह 23 सितंबर के चुनाव में विजेता बन कर उभरे। उन्होंने यामीन को करारी शिकस्त दी और पर्यटन के लिए लोकप्रिय इस देश में महीनों से चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर शांत लगा दिया।

मालदीव में राजनीतिक संकट फरवरी में आपातकाल लगाए जाने और यामीन के सौतेले भाई गयूम सहित विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाले जाने के साथ शुरू हुआ था। यामीन ने चुनाव नतीजों को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव में धांधली हुई है। लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नतीजों को कायम रखा। सत्ता का हस्तांतरण 17 नवंबर को

होना है। गयूम (80) ने एक साक्षात्कार में कहा कि पिछले कुछ बरसों में मालदीव की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है, सरकार पर मालदीव के लोगों का भरोसा भी हिला है। यह पूछे जाने पर कि क्या यामीन ने चीन से समर्थन मिलने पर सियासी ताकत हासिल की, इस पर गयूम ने आशा जताई कि चीन मालदीव के अवाम की इच्छाओं का सम्मान करेगा।

भारत के साथ संबंध मजबूत करने का श्रेय गयूम को जाता है। उन्होंने ईमेल पर दिए साक्षात्कार में कहा, ''चीन ने हमारे विकास के लिए जो सहायता की है, उसे हम मानते हैं। हालांकि, हाल के बरसों में हम पर जो कर्ज बढ़ा है उसे लेकर हम चिंतित हैं और यह महसूस करते हैं कि इसकी सावधानी से समीक्षा तथा प्रबंधन करने की जरूरत है। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि चीन मालदीव के लोगों की इच्छा का सम्मान करेगा।''

फरवरी में यामीन द्वारा आपातकाल लागू किए जाने के बाद भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर गयूम ने कहा, ''भारत ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई और लोकतंत्र बहाल करने के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काफी दबाव बनाया।'' गौरतलब है कि पांच फरवरी को यामीन द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा किए जाने के बाद मालदीव के साथ भारत का संबंध तनावपूर्ण हो गया। हालांकि, 45 दिन बाद आपातकाल हटा दिया गया।

गयूम ने कहा, ''मुझे ऐसा नहीं दिखता कि पिछले कुछ बरसों में (द्विपक्षीय संबंधों पर) देर तक टिकने वाला प्रभाव पड़ा है...मुझे नहीं लगता कि ये उथल पुथल और संकट दशकों पुरानी भारत प्रथम की नीति (हमारी) को प्रभावित करेगा।'' उन्होंने भारत को मालदीव का करीबी और सबसे भरोसेमंद सहयोगी देश करार देते हुए कहा कि यह मालदीव के सभी पड़ोसियों के हित में है कि हिंद महासागर में स्थिरता रहे। उन्होंने कहा, ''हम भारत और अन्य देशों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहेंगे।''

उन्होंने कहा कि उनका देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत जल्द मालदीव की यात्रा पर स्वागत करने की आशा करता है। मालदीव में सत्ता के हस्तांतरण के बारे में पूछे जाने पर गयूम ने कहा कि मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाने के लिए यामीन के पास कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सुगमता से सत्ता हस्तांतरण होने का रास्ता साफ है।

सार समाचार

पाकिस्तान में टीवी चैनलों पर भारतीय कंटेंट दिखाने पर फिर से रोक

कराची। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को लाहौर उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश को पलटते हुए देश के टीवी चैनलों पर भारतीय कंटेंट प्रसारित करने पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। डॉन' समाचारपत्र की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) साकिब निसार यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक मामले पर सुनवाई कर रहे थे। यह मामला उच्चतम न्यायालय की कराची रजिस्ट्री में देश के टीवी चैनलों पर विदेशी कंटेंट के प्रसारण से जुड़ा हुआ था।

खबर में बताया गया कि शीर्ष न्यायाधीश ने गुस्से में कहा, 'वह हमारे बांध के निर्माण में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनके चैनलों पर भी रोक नहीं लगा सकते?' उन्होंने भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण को 'बंद करने' और अधिकारियों को 'सिर्फ उचित कंटेंट प्रसारित' करने के आदेश दिए। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक अधिकरण (पीईएमआरए) ने 2016 में स्थानीय टीवी और एफएम रेडियो चैनलों पर भारतीय कंटेंट प्रसारित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था।

भारत में मनोरंजन उद्योग एवं कुछ चैनलों ने भी पाकिस्तानी कंटेंट एवं कलाकारों के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए थे और इस फैसले को जैसे को तैसा कदम के तौर पर देखा जा रहा था।

खबर में बताया गया कि लाहौर उच्च न्यायालय ने 2017 में पीईएमआरए द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को यह कहते हुए हटा दिया था कि 'विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है' और संघीय सरकार के आपत्ति नहीं दर्ज कराने के चलते इसे अमान्य ठहरा दिया था।

यहूदी प्रार्थना स्थल पर गोलीबारी के बाद पिट्सबर्ग जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप

मर्फीसबोरो (अमेरिका)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह पेनसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग शहर जाएंगे जहां एक बंदूकधारी ने यहूदियों के प्रार्थना स्थल पर गोलीबारी कर 11 लोगों की हत्या कर दी है।

नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले प्रचार रैली के लिए इलिनियोस में मौजूद ट्रंप ने गोलीबारी की घटना को देखते हुए इस दौरे की योजना बनाई जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने इस हमले को 'दुष्प्रभाव किया गया यहूदी विरोधी हमला' और 'मानवता पर हमला' बताया। ट्रंप ने ट्वीट किया,' पूरा अमेरिका यहूदी अमेरिकियों की हत्या पर शोकाकुल है।'

पिट्सबर्ग में हुआ हमला यहूदी विरोधी घृणा अपराध: एंजेला मर्केल

बर्लिन। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने शनिवार को अमेरिका के पिट्सबर्ग में यहूदियों के प्रार्थना स्थल पर हुई घातक गोलीबारी को फ्घोर यहूदी विरोधी घृणा अपराध' बताते हुए उसकी निंदा की है। जर्मनी सरकार के एक प्रवक्ता ने मर्केल के बयान को ट्वीट किया जिसमें कहा गया, 'यहूदी विरोधी विचारों के खिलाफ हम सबको, हर जगह खड़ा होना होगा।' शहर के जन सुरक्षा निदेशक वेंडेल हिसरिच ने बताया कि इस गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। जांच एजेंसी एफबीआई मामले की जांच घृणा अपराध के तौर पर कर रही है। अपने खुद के देश में प्रबल हो रहे यहूदी विरोधी विचारों का सामना कर रही मर्केल ने कहा कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है और उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

26 जनवरी के समारोह में नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप : रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आने में असहमति जताई है। अगस्त महीने में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने मीडियाकर्मियों से कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को चीफ गेस्ट के लिए भारत की तरफ न्योता आया है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल इस बारे में आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। वर्तमान में इस यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि प्रेसिडेंट की यात्रा के बारे में व्हाइट हाउस के अधिकारी ही बयान दे सकते हैं।

दरअसल, पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी महीने में होने वाले रिपब्लिक डे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जनवरी महीने में 'स्टेट ऑफ द यूनियन ऐड्रेस' प्रस्तावित है। ट्रंप उस कार्यक्रम में व्यस्त होंगे।

जानकारी के लिए बता दें कि बराक ओबामा राष्ट्रपति रहते हुए दो बार भारत की यात्रा पर आए थे। दूसरी बार की यात्रा (2015) में वे रिपब्लिक डे पर बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। उस दौरान भी जनवरी महीने में उनका 'स्टेट ऑफ द यूनियन ऐड्रेस' कार्यक्रम होनेवाला था। 'स्टेट ऑफ द यूनियन ऐड्रेस' कार्यक्रम में हर साल जनवरी महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से आनाकानी को भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते में खटास के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक फोरम पर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं और गहरे दोस्त की तरह बर्ताव करते हैं।

शिंजो आबे ने कहा, मोदी मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे ÷विश्वसनीय÷ दोस्तों में से एक हैं और भारतीय नेता के साथ मिलकर वह हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को खुला एवं मुक्त बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करना चाहेंगे। जापान में दोनों नेताओं के बीच होने वाली शिखर बैठक वाले दिन भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित एक संदेश में आबे ने कहा कि भारत एक वैश्विक शक्ति के तौर पर क्षेत्र एवं विश्व समृद्धि को प्रबल बना रहा है।

जापानी प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महान देश के एक उत्कृष्ट नेता हैं। उन्होंने कहा, ÷मेरा हमेशा से मानना रहा है और मैंने कहा है कि जापान एवं भारत के बीच के संबंध विश्व में सबसे बड़ी संभावना से समृद्ध है।÷ आबे ने कहा कि जापान और भारत का सहयोग सुरक्षा, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, 'हम सभी क्षेत्रों में अच्छी स्थिति में हैं और जापान भारत की आर्थिक वृद्धि और उसकी (जापान की) विश्व अग्रणी तकनीकों का इस्तेमाल कर हाई-स्पीड रेल, भूमिगत मार्गों एवं अन्य अवसंरचनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक-इन-इंडिया पहल को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।'

आबे ने कहा कि जिस दिन सहयोग के माध्यम से

जापानी शिंकनसेन बुलेट ट्रेनें मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ेंगी वह दिन भारत-जापान की भविष्य में दोस्ती का चमकता हुआ संकेत होगा। जापानी नेता के संदेश में कहा गया, 'कल से जापान के दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक हैं। पूरी जापान सरकार की ओर से गर्मजोशी से उनका स्वागत करना मेरा सौभाग्य है।' आबे ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मैं खुले एवं मुक्त हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान-भारत के सहयोग को मजबूत करना चाहूंगा।'

भगोड़ों के मुद्दे पर भारत, ब्रिटेन के बीच बढ़ा है सहयोग

लंदन (एजेंसी)।

ब्रिटेन में भारत के निवर्तमान उच्चायुक्त वाई के सिन्हा का मानना है कि वह अपना कार्यकाल ऐसे समय में समाप्त कर रहे हैं जब भारतीय कानून प्रणाली से भाग कर ब्रिटेन में शरण मांगने वाले भगोड़ों जैसे विवादित मुद्दों पर दोनों देशों की सरकारों के बीच पहले से अधिक सहयोग बढ़ा है। इस महीने 37 साल के बाद भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) से सेवानिवृत्त हो रहे वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि यह उन क्षेत्रों में से एक है जिनमें यह सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद सुधार हुआ है कि लोग भारत में न्याय से बचने के लिए ब्रिटेन में मिलने वाली स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करें। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, ÷न्याय से भागने वाले भगोड़ों जैसे मुद्दों पर मेरा मानना है कि हमारी स्थिति सराहनीय रही है और निश्चित तौर पर हमारी एजेंसियां एवं सरकारों के बीच पहले से अधिक सहयोग देखने को मिला है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग भारत में कानून से बच निकलने के लिए स्वतंत्रता एवं कानून प्रणाली का दुरुपयोग न करें।÷

शाही जोड़ा प्रिंस हैरी और मेगन पहुंचे न्यूजीलैंड

वेलिंग्टन (एजेंसी)।

ब्रिटिश शाही दंपती राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेगन अपनी 16 दिवसीय दक्षिण प्रशांत यात्रा के क्रम अब न्यूजीलैंड पहुंच गये हैं, जहां रविवार को परंपरागत माओरी रीति रिवाजों के मुताबिक उनका स्वागत किया गया। शाही जोड़ा न्यूजीलैंड में चार दिन प्रवास करेगा और इस अवधि में वह प्रधानमंत्री जेसिंडा अरडर्न से मुलाकात करने के अलावा नेशनल पार्क में सैर के लिए जायेगा और सिने उद्योग की बारीकियां सीख रहे युवाओं से मुलाकात करेगा। उनका यहां के राष्ट्रीय पक्षी किवी प्रजनन केंद्र का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। गौरतलब है कि माओरी न्यूजीलैंड के मूल आदिवासी लोग हैं। ससेक्स के ड्यूक प्रिंस हैरी और डचेस मेगन ने माओरी रीतिरिवाज 'होंगी' में हिस्सा भी लिया। इस रस्म में एक दूसरे की नाक से नाक दबा कर सांस भरी जाती है। उनके स्वागत में माओरी समुदाय का परंपरागत हाका नृत्य भी किया गया। ब्रिटिश राजसी परिवार के इस युगल की भ्रमण सूची में आस्ट्रेलिया, फिजी और टोगो भी शामिल है।

अमेरिका में यहूदी प्रार्थना सभा पर हमला, अमानवीय कृत्य : पोप फ्रांसिस

वेटिकन सिटी (एजेंसी)।

अमेरिका के यहूदी प्रार्थना गृह में हुए घातक हमले को पोप फ्रांसिस ने रविवार को ''हिंसा का एक अमानवीय कृत्य'' करार दिया है। पोप ने ऐसा कह कर यहूदी समुदाय के प्रति अपनी एकजुटता भी दिखायी है। अमेरिका के यहूदी प्रार्थना गृह में एक संदिग्ध ने घुस कर शनिवार को गोली मार कर 11 लोगों की हत्या कर दी. जिस समय यह घटना हुई उस वक्त वहां बच्चे के नामकरण संस्कार से संबंधित समारोह का आयोजन किया गया था. पकड़े गए संदिग्ध के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है. अमेरिका के हाल के इतिहास में यह पहला घातक यहूदी विरोधी हमला है.

सेंट पीटर्स स्क्वायर में प्रार्थना के बाद पोप ने कहा, ''वास्तव में हिंसा के इस अमानवीय कृत्य से हम सभी घायल हुए हैं.'' पोप ने कहा, ''ईश्वर हमें समाज में विकसित नफरत की आग को समाप्त करने, मानवता की भावना को मजबूत करने, नैतिक और नागरिक मूल्यों तथा जीवन के प्रति सम्मान एवं ईश्वर के प्रति भय को दूर करने में मदद करें.'' बताया जाता है कि हमले से पूर्व हमलावर रॉबर्ट बोअर्स (46) भवन में घुसा और चिल्लाया ''सभी यहूदियों को मर जाना चाहिए,'' इसके बाद उसने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 11 लोग मारे गए और छह घायल हो गए. इस बीच अमेरिका के पेनसिल्वेनिया के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस ने एक बयान में कहा कि हमलावर रॉबर्ट बोअर्स के खिलाफलगे आरोपों में धार्मिक मान्यताओं को मानने में रुकावट पैदा करने के परिणामस्वरूप किसी की मौत हो जाने से जुड़े 11 आरोप और हिंसा के किसी अपराध में हत्या करने के लिए बंदूक के उपयोग से जुड़े 11 आरोप लगाए गए हैं.

श्रीलंका: राष्ट्रपति ने कहा, विक्रमसिंघे ने कानून-व्यवस्था बर्बाद कर दी थी

कोलंबो (एजेंसी)।

श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने रविवार को कहा कि ''उद्दंड'' बर्ताव के चलते रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त किया गया और कहा कि महिंदा राजपक्षे को संविधान के अनुरूप नया प्रधानमंत्री बनाया गया है. शुक्रवार की रात को विक्रमसिंघे की नाटकीय बर्खास्तगी के बाद राष्ट्र के नाम अपने पहले पैगाम में सिरीसेना ने कहा कि 2015 में अपनी जीत के बाद से विक्रमसिंघे की राजनीतिक आचार-व्यवहार नामुनासिब था. श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा, ''वे श्रीलंका के भविष्य को अपने इर्दगिर्द के ऐसे लोगों की मंडली के लिए मौज-मस्ती की चीज समझते दिखे जिन्हें आमजन की सोच की जरा भी समझ नहीं है.''

सिरीसेना ने आरोप लगाया, ''उन्होंने सुशासन की अवधारणा को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया जबकि भ्रष्टाचार और बरबादी हर तरफ आम हो गई. उन्होंने कहा, ''नीतिगत मामलों हम दोनों के बीच विशाल अंतराल था. मैं मानता हूं कि हमारे बीच के सांस्कृतिक और नीतिगत मतभेद ने इस राजनीतिक एवं आर्थिक संकट में योगदान किया. ''

अपने संबोधन में सिरीसेना ने सेंट्रल बैंक बॉंड घोटाले पर विक्रमसिंघे पर तीखा हमला किया जिसमें उनके मित्र अर्जुन महेन्द्रन पर आरोप लगाए गए थे. महेन्द्रन की नियुक्ति भी विक्रमसिंघे ने ही की थी. उन्होंने कहा, ''बॉंड घोटाले के चलते देश अभूतपूर्व आर्थिक में फंस गया.''

सिरीसेना ने विक्रमसिंघे पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी हत्या की कथित साजिश को बहुत हल्के ढंग से लिया. उन्होंने कहा, ''मुझे सूचना मिली के जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जान-बूझ कर अटार्नी जनरल के विभाग के अधिकारियों से मुलाकात से बच रहे थे. '' उन्होंने विक्रमसिंघे के इस आरोप को खारिज कर दिया की उनकी बर्खास्तगी असंवैधानिक और अवैध है.

रिक्शा चालक के खाते में आए 3 अरब रुपये, पता चला तो थर-थर कांपने लगा

कराची (एजेंसी)।

अपनी बेटी के लिए 300 रुपये में घिसी हुई टायर वाली एक साइकिल खरीदने के लिए साल भर पैसे जमा करने वाला एक रिक्शा चालक अपने बैंक खाते से तीन अरब रुपये (पाकिस्तानी मुद्रा) का हस्तांतरण हुआ देख कर दंग रह गया. वह अपने इस खाते का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था. धन शोधन (मनी लार्उड्रिंग) गतिविधियों का शिकार बने मोहम्मद रशीद नाम के 43 वर्षीय रिक्शा चालक ने बताया, ''मैं यह सब देख कर पसीने से तर-बतर हो गया और थर-थर कांपने लगा. '' गौरतलब है कि पाकिस्तान के नये प्रधानमंत्री इमरान खान ने धन शोधन की गतिविधियों पर रोक लगाने का संकल्प लिया है.

रशीद को जब संघीय जांच एजेंसी से एक फोन कॉल आया तब उसने छिपने की सोची, लेकिन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के समझाने बुझाने पर वह अधिकारियों के साथ सहयोग करने को तैयार हो गया. सिर्फ उसका ही मामला नहीं, बल्कि हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी अखबारों में ऐसी कई घटनाएं प्रकाशित हुई हैं.

इस तरह की घटनाओं के तहत किसी गरीब व्यक्ति के काफी समय से इस्तेमाल नहीं किए गए खाते में काफी रकम आ जाती है और अचानक ही यह हस्तांतरित भी हो जाती है. इस तरह, करोड़ों डॉलर देश से बाहर चला जाता है. रशीद इस मामले में आखिरकार दोषमुक्त हो गया है लेकिन उसकी बेचैनी बरकरार है.

उन्होंने बताया, ''मैंने अपना किराये का रिक्शा सड़कों पर चलाना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे डर है कि कुछ अन्य जांच एजेंसियां मुझे उठा सकती हैं. '' रशीद ने बताया कि तनाव के चलते उनकी पत्नी बीमार पड गई. दरअसल, चंद पलों के लिए बेशुमार दौलत पाने के कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने अपनी बेटी के लिए 300 रुपये में घिसी हुई टायर वाली एक साइकिल खरीदी थी.

पाकिस्तान की खस्ताहाल होती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर नव निर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश से बाहर भेजे गए अरबों डॉलर वापस लाने को संकल्प लिया है. उन्होंने बुधवार को टीवी पर अपने संबोधन में कहा, ''यह आपसे चुराया हुआ धन है. मैं इस देश में किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं बख्शूंगा.''

सूरत। विजय लक्ष्य 2019 के कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया।

सूरत। रंग उपवन चौक बाजार से एकता यात्रा का शुभारंभ हुआ।

कबाड़ वाले का बच्ची के साथ छेड़छाड़ का प्रयास

सूरत। शहर के गोपीपुरा क्षेत्र में एक कबाड़ वाले ने मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। हांलाकि वह अपने प्रयास में सफल हो इससे पहले एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। पकड़े जाने के डर से बच्ची को वहीं छोड़ कबाड़ वाला फरार हो गया। पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने कबाड़ वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। जानकारी के अनुसार सूरत के गोपीपुरा क्षेत्र में एक कबाड़ी रेहडी लेकर आया था। उस वक्त 7-8 साल की बच्ची को देख उसकी नीयत खराब हो गई और उसे बहला फुसलाकर कबाड़ी बच्ची को लेकर एकांत स्थल पर पहुंचा। हांलाकि कबाड़ी बच्ची के साथ कोई नीच हरकत करे उससे पहले वहां से गुजर रहे व्यक्ति ने उसे देख पकड़े जाने के डर से कबाड़ी फरार हो गया। अचानक कबाड़ी के भाग जाने से बच्ची को भी कुछ गलत होने की आशंका हुई और भागकर अपने माता-पिता के पास पहुंच गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि कबाड़ी बच्ची को अपने साथ ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बच्ची से एकांत स्थल की ओर जाने का इशारा करता है। जिसकी कुछ मिनटों के बाद बच्ची एकांत स्थल से भागते हुए बाहर आते दिखाई देती है। घटना से भयभीत बच्ची के परिवार पहले तो मामले की शिकायत करने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन स्थानीय लोगों के समझाने के बाद आखिरकार कबाड़ी के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने आरोपी कबाड़ी की तलाश शुरू कर दी।

दिनेश बांभणिया के आरोपों को पास ने खारिज किया

सूरत । सूरत पास कन्वीनर धार्मिक मालविया ने पास के पूर्व कन्वीनर दिनेश बांभणिया के हार्दिक पटेल पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। मालविया ने दिनेश बांभणिया के आरोपों को पाटीदार समाज के आंदोलन को तोड़ने का एक प्रयास बताया7 मालविया ने कहा कि दिनेश बांभणिया को पहले अपना रुख साफ करना चाहिए, उसके बाद ही हार्दिक पटेल पर आरोप लगाने चाहिए। पिछले साढ़े तीन साल से हार्दिक पटेल पाटीदार आरक्षण आंदोलन को चला रहे हैं, जिनके खिलाफ अनर्गल आरोप उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी 31 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर और पाटीदारों का वर्चस्व कम दिखाने के उद्देश्य से आंदोलन को तोड़ने का प्रयास है7 एक ओर दिनेश बांभणिया कहते हैं कि हार्दिक पटेल को कोई तकलीफ नहीं है, दूसरी ओर अस्पताल के बिल का भुगतान का दावा कर रहे हैं। मालविया ने कहा कि आरोप लगाने वाले को पहले अपना रुख साफ करना चाहिए।

इन्फोर्मेशन, कम्युनिकेशन एन्ड टेलिकॉ युनिकेशन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को लेकर सूरत मनपा का सम्मान

सूरत। भारत सरकार के इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम में सूरत महानगर पालिका को कार्य की सराहना करते हुए तीन अवार्ड से नवाजा गया। इन्फोर्मेशन, क युनिकेशन एन्ड टेलिकॉ युनिकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को लेकर सूरत महानगर पालिका का चयन किया गया। इन्डिया मोबाइल कांग्रेस जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टेलिकॉम फोरम ने पालिका को अवार्ड प्रदान किया। नई दिल्ली के एरोसिटी में 25 से 27 अक्टूबर के दौरान आयोजित समोराह में क युनिकेशन का स्वतंत्र प्रभार संभालनेवाले मंत्री मनोज सिंहा के हाथों 26 अक्टूबर को सूरत महानगर पालिका को अवार्ड प्रदान किया गया।

अवार्ड शहर और पालिका द्वारा नवीनतम कार्य को लेकर दिया गया। इसमें स्मार्टसिटी, डिजीटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इन्टेलिजेंट ट्रान्सपोर्ट, मोबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन सेन्टर, इन्टेलिजेंट ट्रान्जिट मैनेजमेन्ट सिस्टम तथा ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की कार्यवाही के लिए पालिका को स मानित किया गया। बेस्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी एडोपशन की केटेगरी के तहत पालिका को अवार्ड के लिए चयनित किया गया। पालिका की आईटीएमएस, आईटी मेक और एटीसीएस के तहत कार्यवाही को केन्द्र सरकार ने सराहा।

सिंचाई घोटाले मामले में कांग्रेस विधायक साबरिया की पूछताछ

अहमदाबाद। मोरबी जिले में करोड़ों रुपये की सिंचाई घोटाला सामने आने के बाद पिछले करीब एक महीने से कई अग्रणी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं तब रविवार को सिंचाई घोटाले की जांच कर रही स्थानीय ए डीविजन पुलिस की टीम ने हलवद के कांग्रेस के विधायक परसोत्तम साबरीया को पूछताछ के लिए बुलाये जाने पर राज नीति में हलचल तेज हो गई है। दूसरी तरफ, यह पूरे घोटाले में आगामी दिनों में अभी चौंकानेवाले खुलासे होने की और कई नई गिरफ्तारी होने की संभावना बढ़ गई है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, मोरबी जिले में छोटी सिंचाई योजना के तहत हलवद, मालिया, मोरबी सहित के तहसीलों में तालाब गहरे करने के लिए और तालाब के रिनोवेशन करने के नाम पर मोरबी जिले के तत्कालीन कार्यपालक इंजीनियर और इसके संबंधित लोग कन्सल्टिंग एजेन्सी के मालिक द्वारा गलत अनुमान और नक्शा बनाकर सरकार को करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी किए जाने से इस मामले में सांसद द्वारा शिकायत की गई थी और बाद में राज्य सरकार की टीमों द्वारा की गई जांच में घोटाले का खुलासा हुआ था। यह शिकायत बाद रिटायर्ड सहायक इंजीनियर सहित कुल चार लोगों को हिरासत में लिया गया था। ए डीविजन पुलिस ने जांच शुरू करके चार आरोपियों को गिरफ्तार करके घोटाले के जड़ तक पहुंचने के लिए १२ से ज्यादा गांवों में स्थल जांच की गई।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी तलाक चालू

दो महिलाओं को पति द्वारा तलाक दिए जाने से खलबली

अहमदाबाद। वलसाड के उमरगांव के संजान में दो मुस्लिम महिलाओं को उनके पति द्वारा कागज लिखकर ३ तलाक दे देने से खलबली मच गई। विशेष करके मुस्लिम महिलाओं में इस घटना की वजह से कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। दूसरी तरफ तीन तलाक का शिकार हुई दोनों मुस्लिम महिलाओं ने स्थानीय प्रशासन को लिखित जानकारी देकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के फैसले के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा दिया है लेकिन इसके बावजूद भी तलाक चालू है, इसे लेकर मुस्लिम महिलाओं में नाराजगी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार, तीन तलाक का शिकार हुई एक महिला को ७ महीने का गर्भ है और इसकी शादी १० महीने पहले हुई थी। महिला की उम्र सिर्फ २१ वर्ष की है। ज बकि अन्य महिला की उम्र सिर्फ २४ वर्ष है। इस तरह एक साथ दो महिलाओं को पति ने तलाक दे देने से मामला चर्चा में आया है। २१ वर्षीय महिला का आरोप है कि इसके पति का संबंध पति की बहन की बेटी के साथ कई समय से है और उन्होंने दोनों ने महिला को कई बार तलाक की धमकी दी थी। महिला ने बताया है कि, मेरी शादी को १० महीने पहले ही हुई है। मेरे पति परिवार को मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहे है। तीन तलाक पर कानून बन गया है, इसे लागू किया जाए अच्छा। मुझे न्याय चाहिए। उल्लेखनीय है कि, केन्द्र सरकार ने संसद में लंबित तीन तलाक को जुर्माना अपराध बनाने वाले बिल को कानूनी रूप देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यहां उल्लेखनीय है कि, संवैधानिक बैंच ने तीन तलाक बिल को रद्द किया। दो न्यायाधीशों ने इसे असंवैधानिक बताया था, एक न्यायाधीश ने पाप बताया। इसके बाद दो न्यायाधीशों ने इस पर संसद को कानून बनाने का कहा गया। संसद में यह बिल लोकसभा में से पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ। इसके बाद इसे कानूनी बनाने के लिए सरकार ने अध्यादेश का रास्ता पसंद किया है।

रेलवे द्वारा आज से सीएमएमटी-राजकोट के बीच त्यौहार विशेष ट्रेन

सूरत। आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भी? को देखते हुए रेलवे द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एवं राजकोट के बीच विशेष ट्रेन चलाई जायेगी। जिसके मुताबिक ट्रेन सं. 01109 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-राजकोट विशेष ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोमवार, 29 अक्टूबर को 14.10 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 5.40 बजे राजकोट पहुँचेगी। यह ट्रेन यात्रा के दौरान दादर, ठाणे, वसई रोड, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद जं., वीरमगाम जं. एवं सुरेन्द्रनगर स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में एसी 3 टियर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे।

एनसीबी ने अमराईवाडी से आरोपी गिरफ्तार

७५ लाख रुपये की प्रतिबंधित दवाईयों का जत्था जब्त किया

७५ लाख कीमत का आल्प्राजोलम सहित की प्रतिबंधित दवाईयों की २२ हजार से ज्यादा गोली का जत्था जब्त

अहमदाबाद। शहर के अमराईवाडी क्षेत्र से एनसीबी के अधिकारियों ने रविवार को निश्चित जानकारी के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार करके इसके पास से प्रतिबंधित आल्प्राजोलम सहित की गोली का बड़ा जत्था जब्त किए जाने से सनसनी मच गई। एनसीबी के अधिकारियों ने प्रतिबंधित दवाईयों की बिक्री और तस्करी का यह राज्यव्यापी या आंतरराज्यव्यापी घोटाला हो सकता है ऐसी आशंका व्यक्त की है और इसके आधार पर अब पूरी जांच को आगे बढ़ा गया है। एनसीबी की टीम ने आरोपी दिलीप परमार के पास से ७५ लाख रुपये की कीमत का आल्प्राजोलम सहित की प्रतिबंधित दवाईयों की २२ हजार से ज्यादा गोली का जत्था जब्त किया गया था। एनसीबी के अधिकारियों द्वारा अहमदाबाद शहर में कुछ समय पहले ही चरस, ड्रग्स सहित के नशीले पदार्थों के बडे कन्साइनमेन्ट का पर्दाफाश करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

शहर में विशेष करके रेलवे स्टेशन या बस स्टेशनों सहित के स्थलों पर नशीले पदार्थ या प्रतिबंधित ड्रग्स -दवाईयों की तस्करी को रोकने के लिए और इसके कन्साइनमेन्ट का पर एनसीबी निजी रूप से इनपुट्स लेती रहती है, इसके तहत एनसीबी के अधिकारियों को निश्चित जानकारी मिली थी कि, प्रतिबंधित दवाईयों के बड़े जत्थे के साथ एक आरोपी अमराईवाडी क्षेत्र में प्राइवेट लकजरी में जा रहा है, जिसके आधार पर एनसीबी के चुने गये अधिकारियों ने गुप्त तरीके से ऑपरेशन को पूरा किया गया और अहमदाबाद से शीरडी जाती एमके. बस सर्विस की लकजरी बस को रोककर इसमें से आरोपी दिलीप परिहार के पास से एक बैग में से प्रतिबंधित आल्प्राजोलम सहित की दवाईयों का बड़ा जत्था मिला था। एनसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार करके इसके विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत जरूरी अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

बिजनेसमेन के पुत्र ने ९वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की

अहमदाबाद। शहर के पालडी क्षेत्र में एक बिजनेसमेन के २० वर्षीय पुत्र ने ९वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेने से सनसनी मच गई। २० वर्षीय साहील शाह निरमा यूनिवर्सिटी से बीबीए की पढ़ाई पूरी करके पिता की रियल एस्टेट कंपनी में सीईओ के तहत शामिल हुआ था और वह परिवार का एक का एक पुत्र था। यह युवक द्वारा अपार्टमेन्ट की ९वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेने की वजह से स्थानीय निवासियों सहित लोगों में शोक की लहर फैल गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। दूसरी तरफ, युवक की आत्महत्या को लेकर कई अटकलें लगाये जा रहे हैं। बिटकॉइन में युवक पर बहुत कर्ज हो गया सहित के कई कारणों पर चर्चा हो रही है लेकिन पुलिस सभी मुद्दे पर जांच करके आगे बढ़ रही है यह वास्तविक कारण जानने की कोशिश की जा रही है। शहर के पालडी क्षेत्र में प्रकृति अपार्टमेन्ट में बिजनेसमेन शैलेनभाई शाह उनकी पत्नी, पुत्र साहील शाह और पुत्री के साथ रहते है। साहील ने निरमा यूनिवर्सिटी से अभी बीबीए की पढ़ाई पूरी की और अपने पिता की रियल एस्टेट कंपनी स्पेस अनलिमिटेड में सीईओ के तहत शामिल हुआ था।

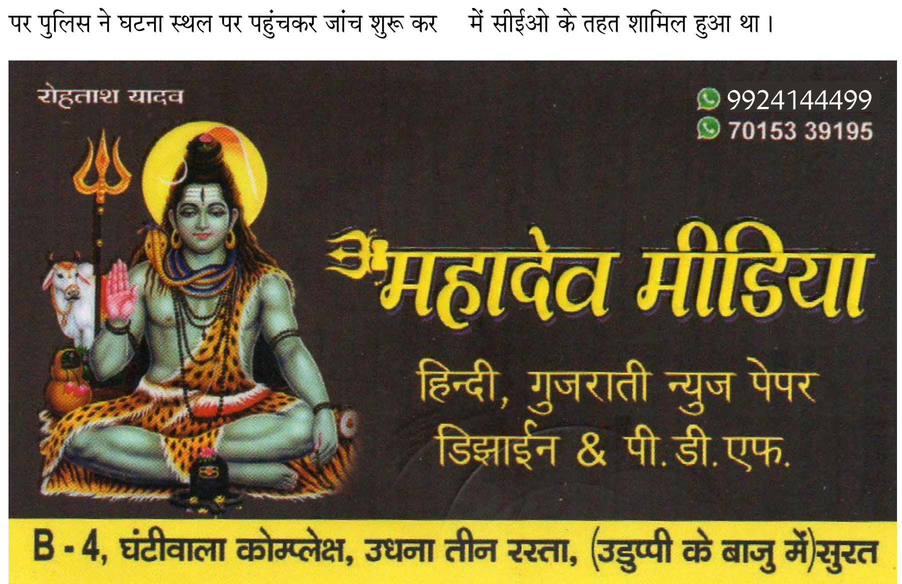

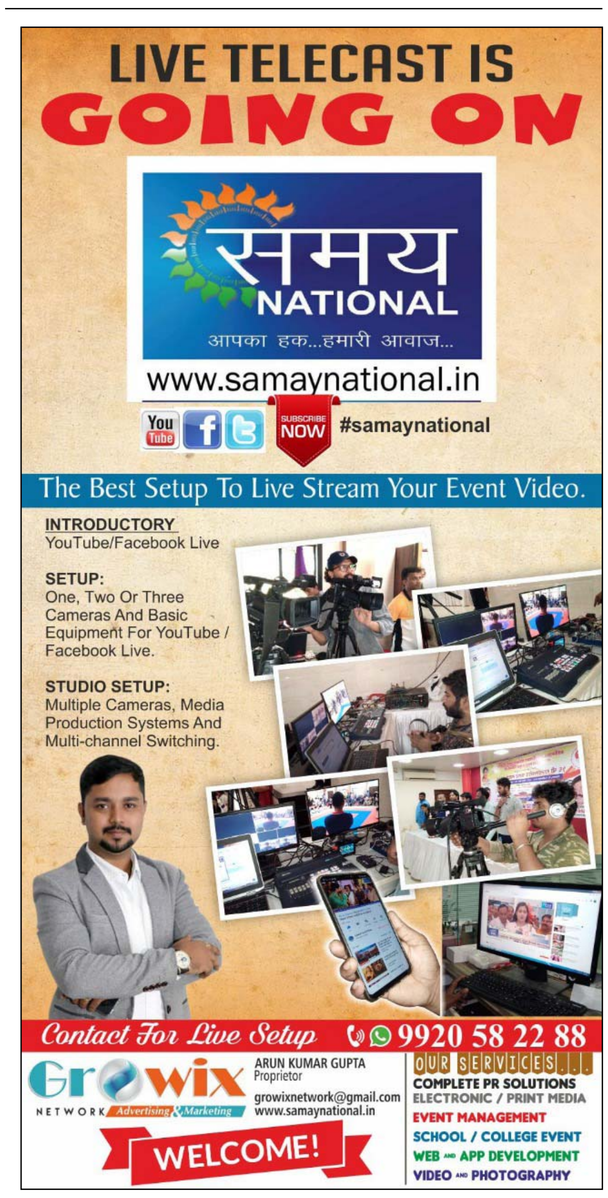

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)